(b) if so, the salient features of the system; and

(c) by when the final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) Yes, Sir. The Government have notified rule entitled "Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness, and Response) Rules, 1996" for management of chemical accidents in the country. According to the provision under Rule-4, initiatives have been taken by the Central Government to set up a Crisis Alert System. The salient features of the system are as follows:

(i) to set up a functional Control Room at the central level alongwith an information networking system with the State and District Control Rooms;

(ii) to furnish the Control Room with the information, namely major accidents hazard installations in the country, major chemical accidents in chronological order, list of members of the Central, State and District Crisis Groups and databases on hazardous chemicals;

(iii) to appoint adequate staff and experts to man the functional Control Room; and

(iv) to take measures to create awareness among the public with a view to preventing chemical accidents.

(c) Does not arise.

Issue of DMS Milk Home Delivery Licences

2346. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether Government issue Home Delivery Licences for milk under the Delhi Milk Scheme (DMS);

(b) if so, the criteria fixed thereof; and

(c) the number of licences issued so far under this scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) and (b) The Delhi Milk Scheme (DMS) issues Home Delivery Cards. These cards are issued only to physically handicapped persons, widow, students and persons with monthly income of below Rs. 300/-.

(c) At present there are 2783 Home Delivery Card holders.

Implementation of CLC's Orders

2347. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Chief Labour Commissioner (CLC) passed an order on 20.1.88 upholding the contention of contract labourers employed by M/s. Harihar Cooperative Labour Contract Society, Khurda Road, Orissa, for parity of wages and-other service conditions with the regular railway employees;

(b) whether the High Court of Orissa and the Supreme Court had dismissed the Writ application and SLP of Union Government respectively against the CLC's orders;

(c) if so, whether the Railways have implemented the CLC's orders;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether any action is being taken to implement the CLC's orders; and

(f) if so, the facts in detail?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the table of Sabha.

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देना

2348. श्रीमती मालती शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों को यह योजना चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार कितनी सहा[illegible]पलब्ध करायी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया): (क) से (घ) शिक्षा विभाग अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

1. अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना और अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को खोलने/सुदृढ़ करने की योजना।

इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित हिन्दी शिक्षकों के पद के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किन्तु यह सहायता केवल एक योजना अवधि के लिए दी जाती है और योजना अवधि समाप्त होने पर इन शिक्षकों को रखने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को अंतरित हो जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान अहिन्दी भाषी राज्यों को ही दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	(लाख रु.) 1995-96
1.	उड़ीसा	174.15
2.	असम	125.06
3.	मणिपुर	92.95
4.	मिजोरम	15.82
5.	आन्ध्र प्रदेश	2.00
6.	नागालैंड	—
		409.98

2. हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

इस योजना के अंतर्गत, हिन्दी के प्रसार-विकास के विभिन्न कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है जैसे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आशुलिपि/टंकण कक्षाएं आयोजित करना, हिन्दी पुस्तकालय खोलना, कार्य विवरणिकाओं/पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि।

सामान्यतया, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन भवनों के निर्माण/मरम्मत/विस्तार के मामले को छोड़कर, जहां अनुदान अनुमोदित व्यय 60% तक अथवा 50,000/- रुपये, जो भी कम हो सकता है, कुल अनुमोदित व्यय के 75% तक दी जाती है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी में प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठनों और व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। व्यक्तियों/स्वैच्छिक संगठनों को हिन्दी पुस्तकों की भारी खरीद के माध्यम से भी सहायता दी जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान इन योजनाओं पर 249.77 लाख रु. का व्यय है। इसके अतिरिक्त उन हिन्दी लेखकों को जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों पर पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसे पुरस्कारों की संख्या 19 प्रति वर्ष है और पुरस्कार राशि 15,000/-रुपये प्रति पुस्तक है।

3. अहिन्दी भाषी व्यक्तियों को हिन्दी का शिक्षण देने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है, तमिल, मलयालम, बंगला तथा अंग्रेजी के माध्यम से अहिन्दी भाषी भारतीयों और विदेशियों को दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण देने के लिए एक पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहा है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी आधारित तथा क्षेत्रीय भाषा आधारित द्विभाषी, त्रिभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोश भी प्रकाशित कर रहा है।

Production of Sugarcane in Bihar

2349. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the production of sugarcane in Bihar during the last three years, yearwise;

(b) whether Government have taken any steps to increase the production and productivity of sugarcane in the State to raise the production of sugar and khandsari; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The production of Sugarcane in Bihar during the last three years i.e. 1993-94,1994-95 and 1995-96 was 44.0, 56.6 & 56.4 lakh tonnes respectively.

(b) Yes, Sir.

(c) To increase the production and productivity of sugarcane, a Centrally Sponsored Scheme on Sustainable Development of Sugarcane Based Cropping System (SUBACS) is being implemented in different States including Bihar besides providing market and